(b) whether Karnataka Government have been pleading for rail expansion and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Expansion of the Railway net-work and gauge conversion from MG/NG to EG is a continuous on-going process. The works are sanctioned during the Railway Budget every year, based on the availability of resources keeping in view the large shelves of ongoing works and the funds required for progressing the same. The Planning Commission had appointed a Committee for Expansion of Railway Network (CERN) and this Committee had identified new lines totalling 2902 kms. gauge conversions totalling 2303 kms., which would be required for meeting th_c transport infrastructure requirements upto the year 2000. The funds required for these lines are of the order of Rs. 4400 crores. The works to b_e taken up in the next 3 years would be identified and sanctioned keeping in view the recommendations of this Committee depend-'ng on the Annual Plan Outlays approved for this Head by the Planning Commission.

(b) No formal request from the State Government has been received in this regard.

Proposal for a day train between Guntur and Secundsrahad

*iW. DR. YELAMANCHILI SIVA-JI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's considerstion to introduce a day-time train between Guntur and Secunderabad and vice-versa via Nadikude in the South Central Railway; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BHAKTA CHARAN DAS):

(a) No, Sir. (b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में डाई-अमोनिया फास्फेट का उत्पादन करने के लिये कारखाना

*137. **कुमारी आलिया :**
श्री अजीत जोगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में डाई-अमोनिया फास्फेट उर्वरक का अभाव रहा है और इस अभाव को आयातों के द्वारा पूरा किया जा रहा है;

(ख) क्या देश में रॉक फास्फेट की अधिकतम मात्रा मध्य प्रदेश से निकाली जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस रॉक फास्फेट की खपत करने के लिए मध्य प्रदेश में एक डाई-अमोनिया फास्फेट का विनिर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना करने का विचार रखती है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) (क) स्वदेशी स्रोतों से फोस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता कुल मांग से कम है। मांग तथा स्वदेशी स्रोतों से उपलब्धता के बीच के अन्तर का आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश से निकाला जा रहा रॉक फास्फेट मात्रा में कम है। निकाले गए रॉक फास्फेट की मात्रा तथा इसका निम्न स्तर डाई-अमोनियम फास्फेट संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है।

स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित की जाने वाली डेरी परियोजनाएं

*138. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विट्जरलैंड के सहयोग

से राज्यों में डेरी परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में किन-किन शहरों में स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वोरचन्दभाई शाह) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है जिसका मूल उद्देश्य सिटअरलैंड सरकार के सहयोग से राज्यों में डेयरी परियोजनायें स्थापित करना हो।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

Uniform code for cooperatives

*1S9. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

■ (a) whether Government propose to have a uniform code and legal rules for the all co-operatives in the country; and

' (b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHAND-BHAI SHAH): (a) and (b) Co-opera, tive Societies" is a State Subject. The Stats Governments are responsible for the supervision of, and guidance to, the co-operative societies in the States. For this purpose, each State Government has enacted its own co-operative societies law.

The Government of India, in the Planning Commission, hav$_e$ appointed a Committee to assess the existing situation of the co-operative movement and nature of co-operative laws, so as to recommend a model for co-operative law in the country. The Committee has prepared a draft Bill, which has been circulated to the State Governments, national-level co-operative societies, agencie$_s$ interested in the promotion of co-operative activities and individual co-operators. The final draft will be prepared by the Committee in the light of these comments and the same is expected to be submitted to the Planning Commission by March, 1991.

उन्नत प्रकार के बीज

*140. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए किस-किस प्रकार के उन्नत बीच उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ख) इन बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों में विभिन्न फसलों की 235 किस्में अधिसूचित की गई हैं।

(ख) बीजों के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों केन्द्र शासित क्षेत्रों की है, जो यह काम विभिन्न राज्य एजेंसियों के द्वारा करते हैं। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय बीज निगम और राजकीय फार्म निगम के जरिये इस काम में उनकी सहायता करती है। फसल विकास कार्यक्रमों के तहत भी इन्हें सहायता दी जाती है।

गरीबी को कम करने के लिये प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों की निष्फलता

@993. **श्री राम जेठ मलानी** :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26

@Previously Unstarred Question No. 933 transferred from l$_s$t January, 1SS1.